विवरण

समेकित चावल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1992–93 में आयोजित कृषक प्रशिक्षण शिविरों तथा उनमें भाग लेने वाले किसानों की संख्या

क्र०सं०	राज्य का नाम	आबंटित प्रशिक्षण शिविरों की संख्या	प्रायोजित प्रशिक्षण शिविरों की संख्या	किसानों की संख्या (लक्ष्य)	भाग लेने वाले किसानों की संख्या
1.	असम	43	—	4300	—
2.	बिहार	85	सू० न०	8500	सू० न०
3.	मध्य प्रदेश	85	19	8500	1900 जनवरी 93 तक
4.	उड़ीसा	78	सू० न०	7800	सू० न०
5.	उत्तर प्रदेश	58	46	5800	1600
6.	पश्चिम बंगाल	40	40	4000	4000
7.	त्रिपुरा	5	1	500	100
8.	आंध्र प्रदेश	2	सू० न०	200	30513
9.	गुजरात	4	1	400	100
10.	महाराष्ट्र	9	सू० न०	900	सू० न०
11.	अरूणाचल प्रदेश	2	सू० न०	200	सू० न०
12.	मेघालय	2	सू० न०	200	सू० न०
13.	नागालैण्ड	2	सू० न०	200	सू० न०

सू० न०—राज्य द्वारा सूचित नहीं ।

Farmers Welfare Fund

3352. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to organise a full fledged Farmers Welfare Fund for the benefit of farmers all over the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, what steps proposed to be taken to create a nation-wise body to look after the welfare of farmers; and

(d) whether Government propose to consider establishing a Pension Fund for Farmers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no proposal to create a nation-wide body to look after the welfare of farmers.

(d) At present, there is no proposal to consider establishing a Pension Fund for Farmers.

Sale of banned Pesticides

3353. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 657 given in Rajya Sabha on 30th July, 1993 and state:

(a) what is the monitoring mechanism to see that the banned pesticides are not sold;

(b) whether Government have received complaints that these are still being sold and manufactured;

(c) how many cases of the violation of ban have been detected; and

(d) what penal action has been taken and on whom?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) State functionaries notified under the 'Insecticides Act', 1968 undertake regular monitoring to ensure that the banned pesticides are not sold.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Questions do not arise.

गन्ना उत्पादकों को लाभ का हिस्सा दिया जाना

3354. श्री राम गोपाल यादव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शीरे पर से नियंत्रण हटाये जाने के पश्चात् चीनी मिलों द्वारा अर्जित लाभ का कुछ हिस्सा गन्ना उत्पादकों को देने का विचार रखती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ताकि गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पादों के अधिकतम लाभ मिल सकें ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) शीरे सहित सह उत्पादों की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त आय को चीनी की अधिसूचित उत्पादन लागत को निश्चित करते समय ध्यान में रखा जाता है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5क में किए गए प्रावधान के अनुसार उपर्युक्त उत्पादन लागत के आधार पर चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अर्जित की गई अतिरिक्त प्राप्तियों को गन्ना उत्पादकों और चीनी फैक्ट्रियों के बीच बांटा जाना अपेक्षित होता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते।

Subsidy on Foodgrains to F.C.I.

3355. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what was the total subsidy on foodgrains given to the Food Corporation of India during the last three years;

(b) what is the differential amount incurred by the F.C.I. between procurement price and selling price for which subsidy is required to be given; and

(c) what is the total administrative cost of F.C.I.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) During the last three years 1990-91, 1991-92 and 1992-93, the following amounts were paid-released by the Government of India to